卐 श्री सदगुरू देवाय नम: 卐 卐ओ३म् 卐 卐 जय माता दी 卐
卐 सीताराम बाबा जी 卐卐जय बाबा की 卐卐श्याम बाबा卐 卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धो: सलिलं सलीलं,य:शोकवह्निं जनकात्मजाया: आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
मनोजवं मारूत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये

केंद्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 66 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ♦शुक्रवार ♦12 दिसम्बर 2025 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

देवभूमि में नहीं पनपने देंगे मुल्लावादी प्रवृति-धामी

भाजपा सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों से कांग्रेस हो रही परेशान

भीमताल (नैनीताल)। विधानसभा क्षेत्र भीमताल में करोड़ो रूपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड राज्य में किसी दशा में मुल्लावादी प्रवृति को पनपने नहीं दिया जायेगा। राज्य में लैंड जेहाद, लव जेहाद व थूक जेहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाये गये हैं। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश में दंगा रोधी कानून शक्ति से लागू किया जा रहा है। इसका उदाहरण देते हुए धामी ने कहा कि बनभूलपुरा हल्द्वानी में सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के दौरान जिन लोगों के द्वारा दंगा किया गया उनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाही की गई कि अब वहां हर कोई सरकारी भूमि पर कब्जा करने से पहले सोचता है। श्री धामी ने कटाक्ष करते हुए कहां कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा सरकार द्वारा उठाए जा रहे सख्त कदमों से परेशानी हो रही है क्योकि उन्होंने ही स्वार्थो के चलते विशेष समुदाय के लोगों को सरकारी भूमि पर बसाया था। उन्होंने कहा कि जंगल के बीच बनायी जा रही अवैध धार्मिक इमारतों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। प्रदेश के विकास में कराये जा रहे कार्यो का जिक्र करते उन्होने कहा कि प्रदेश आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और उनके मार्ग दर्शन में निरंतर विकास और समृद्धि में नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उन्होने कहा आज भीमताल विधान सभा के क्षेत्र के करोड़ों रूपये की लागत को विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही(शेष पृष्ठ सात पर)

धामी ने नैनीताल जिले को दी 112 करोड़ की सौगात

17 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

भीमताल(उद संवाददाता)।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को धारी ब्लॉक स्थित हिमगिरी स्टेडियम लेटीबुंगा में पहुंचे। जहां सीएम ने जिले की 112.34 करोड़ की 17 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी ने 70.73 करोड़ की लागत से 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 4.53 करोड़ से सेनिटोरियम से अल्मोडा मार्ग तक भवाली बाईपास भाग-1 का डामरीकरण,

11.62 करोड़ से भवाली-सेनिटोरियम से नैनीबैंड तक भवाली बाईपास पार्ट-2 सुधारीकरण, 7.95 करोड़ से भीमताल बाईपास मोटर मार्ग का सुधारीकरण, 16.62 करोड़ भीमताल-खुटानी -चांफी-परमपुरी-धानाचुली पंचेश्चर मोटर(शेष पृष्ठ सात पर)

दर्दनाक हादसा-दो युवकों की मौत,पांच गंभीर घायल

रामनगर। उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। शुक्रवार तड़के हल्द्वानी-बाजपुर मार्ग पर गड़प्पू क्षेत्र में एक और भीषण दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग और दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गाजियाबाद से नैनीताल की ओर जा रही टाटा टियागो कार(UP 14 GN 4349) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह लगभग 7:30 बजे गड़प्पू चौकी के कांस्टेबल मिथुन कुमार ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निजी वाहन से बाजपुर अस्पताल ले जाया गया। जबकि दो गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 108 द्वारा सीएचसी कालाढूंगी पहुंचाया गया, जहां(शेष पृष्ठ सात पर)

आवश्यकता है

रूद्रपुर में न्यूज चैनल के लिए एक वीडियो एडिटर की अवश्यकता है।
-: शीघ्र सम्पर्क करें:-
मो. 9897427586

भूमियाधार में दो नाली में बनी मस्जिद की आड़ में 43 नाली भूमि कब्जाई ?

वन विभाग, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल

नैनीताल। भवाली क्षेत्र में भूमिया धार रोड पर बनी मस्जिद की आड़ में करीब 43 नाली सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर उसकी चार दीवारी बना ली है? इस मामले में वन विभाग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे है कि आखिर आरक्षित वन क्षेत्रों में ये संरचनाएं कैसे और क्यों बन रही है और इनका विस्तार भी कैसे हो रहा है ? जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है उक्त मस्जिद जंगल की भूमि पर बनाई गई है और धीरे धीरे मस्जिद प्रबंधन ने आसपास की भूमि पर कब्जा कर लिया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने इस मामले के संज्ञान में आने के बाद उक्त मस्जिद स्थल पर राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम भेजी और पाया कि करीब 45 नाली भूमि पर चारदीवारी कर मस्जिद का परिसर बनाया हुआ है। इस मामले में वन विभाग ने अपने नक्शे देखने के बाद बताया कि उक्त मस्जिद के लिए वन विभाग द्वारा 1924 में 5016 वर्गफुट(दो नाली पांच मुट्ठी) जमीन लीज पर दी गई थी। खास बात ये कि उक्त लीज अवधि भी कई साल पहले समाप्त हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में ये 45 नाली से अधिक बताई गई है , यानि करीब 43 नाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा स्पष्ट दिखाई दे रहा है ? इस क्रम में जब राजस्व विभाग के दस्तावेज देखे गए तो 45 नाली भूमि नगर पालिका के दस्तावेजों में दर्शाई गई है।बड़ा सवाल ये है 2 नाली से 45 नाली कैसे हो गई? जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के मुताबिक इस विषय पर अभी और जांच पड़ताल की जा रही है कि कितनी और कब कब ये संरचना बनी और परिसर ने कैसे विस्तार पाया ? हम ने वन विभाग के डीएफओ को समस्त भू दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट देने को कहा है। बरहाल नैनीताल जिले में सरकारी भूमि अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर प्रशासनिक जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है । जानकारी के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव आर के सुधांशु ने भी इस मामले में नैनीताल जिला प्रशासन से बात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी धार्मिक संरचनाएं हटाई जा रही है। हम इस देवभूमि के देव सांस्कृतिक स्वरूप को किसी भी हाल में बदलने नहीं देंगे। भूमियाधार जंगल में मस्जिद मामले की विधिक जांच पड़ताल कराई जा रही है।

रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जा कर बना डाली बड़ी मस्जिद

वन विभाग ने सभी धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर खाली करायी जमीन

रामनगर। नैनीताल जिले में रामनगर कोसी नदी किनारे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन कब्जा कर बड़ी मस्जिद बना डाली। तीन दिन पहले हुई धामी सरकार की कारवाई में उक्त मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया। वन विभाग ने इससे पूर्व उक्त धार्मिक संरचना को हटाए जाने का नोटिस जारी किया था।कोसी नदी किनारे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को कब्जाने और वहां पुछड़ी बस्ती बनाने में ताहिर मुला, सलीम पत्रकार, अंकल,बाबू, और इनके राजनीतिज्ञ आकाओं के नाम सामने आए और वीडियो भी वायरल हुए, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं अवैध कब्जा करने वालों से बाते करते हुए वीडियो रिकार्डिंग की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे और कितने पैसों में हमने किस किस से जमीन खरीदी।वन विभाग ने पुछड़ी बस्ती में करीब 64 एकड़ भूमि पहले चरण में खाली करवाई है जबकि अगले चरण में लगभग 100 एकड़ वन भूमि खाली करवाई जानी है। धामी सरकार ने कारवाई के दौरान ये भी पाया कि झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने कैसे हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की और इसका खर्च कौन कौन उठा रहा था ? वेस्टर्न सर्कल के मुख्य वन संरक्षक डॉ साकेत बडोला ने बताया कि वन विभाग हाई कोर्ट में इन अवैध कब्जेदारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई में भी तेजी लाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कर चुका है।दरअसल यहां घुसपैठियों को बाहरी राज्यों से लाकर उन्हें बसाने उनसे पैसा लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का षडयंत्र यहां पिछले कुछ सालों से लगातार चल रहा था।इस मामले की धामी सरकार ने एसआईटी जांच भी करवाई थी। सरकार का ये मानना भी है कि यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोगों को कब्जे करवाए गए और अब यहां डेमोग्राफी चेंज की समस्या ने सिर उठा लिया।कोसी नदी किनारे रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर कब्जा कर योजनाबद्ध तरीके से छोटा मंदिर, मजारे, मदरसे और एक बड़ी मस्जिद भी बना दी गई। सात दिसंबर की सुबह भारी फोर्स लेकर वन विभाग ने पहले चरण की कारवाई करते हुए उक्त धार्मिक संरचनाएं भी साफ कर दी।जानकारी के मुताबिक दो हजार वर्ग फुट से अधिक सरकारी वन आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से बड़ी मस्जिद बना दी गई जिसे भी ध्वस्त कर दिया गया। डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि वन विभाग के आरक्षित क्षेत्र की भूमि को खाली करवाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण वन आरक्षित क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस जारी किए है कि अतिक्रमण करने वाले स्वयं ही अवैध कब्जा छोड़ दे अन्यथा वन विभाग और प्रशासन ये कारवाई अवश्य करेगा।वन विभाग ने फिलहाल मुक्त करवाई गई आरक्षित वन भूमि को तारबाड़ से सुरक्षित करने का काम शुरू करवा दिया है।

वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा: सीएम

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन-प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अन्दर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए।मुख्यमंत्री ने पौड़ी में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिये हैं।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का अधिक भय है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। मानव-वन्यजीव संघर्ष में किसी परिवार से कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनके परिवार

को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए दो सप्ताह के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की आवश्यकता है, उन्हें यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी वन्यजीवों से लोगों के जीवन को बचाना है, इसके लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया जाए। जंगली जानवर आबादी क्षेत्रों में न आये, इसके लिए स्थाई समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाए। वन्यजीवों की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से निरंतर नजर बनाये रखें। वन कर्मी लगातार निगरानी रखें, साथ ही ग्रामीणों के साथ अपना संवाद मजबूत रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तियों के आस पास जंगली झाड़ियों को अभियान चलाकर साफ किया जाए, साथ ही बच्चों और महिलाओं को विशेष तौर पर आस पास वन्य जीवों की मौजूदगी को लेकर जागरूक किया जाए। बैठक में वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव श्री आरके सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री विनय शंकर पांडेय, सी रविशंकर, प्रमुख वन संरक्षक श्री रंजन मिश्रा, अपर सचिव हिमांशु खुराना शामिल हुए।

राज्य की सभी जेलों में 'एक जेल-एक प्रोडक्ट' का मॉडल विकसित करें

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में जेल विकास बोर्ड बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य की सभी जेलों में 'एक जेल-एक प्रोडक्ट' का विकास किया जाए। कारागारों में निरूद्ध बन्दियों के कौशल विकास हेतु नियमित कार्यक्रम आयोजित किये जाएं। आईटीआई के माध्यम

से भी जेलों में अलग-अलग ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।उन्होंने कहा कि जेलों के विकास के लिए राज्य का अपना अलग मॉडल विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जेलों में बनाये गये उत्पादों का सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे समय-समय पर जेलों में भोजन व्यवस्थाओं को भी देखें। बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कारागार सितारगंज, जिला कारागार अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, उप कारागार हल्द्वानी और रूड़की में लॉड्री मशीन की स्थापना की जायेगी। जिला कारागार देहरादून और हरिद्वार में इसकी स्थापना से अच्छे परिणाम आये थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कारागारों में चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रदेश की खुली जेल सितारगंज में कच्ची घानी सरसों तेल संयंत्र की स्थापना पर सहमति बनी। सितारगंज और हरिद्वार जेल में मशरूम फार्मिंग की सहमति भी दी गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिला कारागार हरिद्वार, अल्मोड़ा, केन्द्रीय कारागार सितारगंज और उपकारागार हल्द्वानी में बेकरी यूनिट की स्थापना से लगभग 12 लाख रूपये आय अर्जित हुई है। सितारगंज खुली जेल में गौशाला की स्थापना से 10 लाख रूपये की आय हुई है। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव गृह श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक कारागार श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री सी. रविशंकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने दी 210 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन कार्यो तथा मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 210 करोड़ से भी अधिक लागत की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपदों की मांग के अनुरूप आपदा में राहत एवं बचाव कार्यों के सफल संचालन हेतु 71 बोलेरो वाहन हेतु 7.24 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु एन.एच.-109 के लगभग 07 कि.मी. लम्बाई के पुन सरेखण के निर्माण हेतु 188.55 करोड़ की योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है।मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा सीएम घोषणाओं से संबंधित कार्यों के लिए ₹14 करोड़ से अधिक की स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। जिनमें जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में हरकोट से थामडी कुण्ड एवं जलथ से फगुनी उड्यार तक सम्पर्क मार्ग हेतु 88.76 लाख, दोबाटा से मर्तोली तक 3.02 कि.मी. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 84.12 लाख, विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में विकासखण्ड मूनाकोट के अंतर्गत ग्राम नैनीपातल से भगवती मंदिर तक सी.सी. सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 45.74 लाख की योजना सम्मिलित है। जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में नाबार्ड मद से औद्यानिकी विकास किये जाने हेतु धनराशि 98.18 लाख तथा पूर्णागिरी तहसील में मिनी विकास भवन/बार भवन के निर्माण हेतु 533.79 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का भी मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के अंतर्गत ग्राम पंचायत काण्डी, चामा, गाता में सार्वजनिक टीन शैड के निर्माण हेतु 55.95 लाख और जनपद उधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में 300 हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु 499.65 लाख की योजना को वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने विकासखण्ड नारसन के ग्राम मुकीमपुर में भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेंट फैक्ट्री के पास बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु सोलानी नदी के बांये किनारे पर सी.सी. द्वारा दो स्पर के निर्माण हेतु 24.37 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी : सीएम

घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला, हड़ताल स्थगित

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुलाकात की। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि जनपद टिहरी गढ़वाल के पिलखी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उच्चीकृत किया गया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस उच्चीकरण के साथ, शासन द्वारा कुल 36 पदों (26 नियमित + 10 आउटसोर्सिंग) का सृजन किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में कोई बाधा न आए और क्षेत्र की जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों। ये सभी पद अस्थायी रूप से 28 फरवरी 2026 तक स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ाया भी जा सकता है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा– "हमारी सरकार का लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को उसी स्तर पर विकसित किया जाए, जैसा मैदानों में उपलब्ध है। पिलखी क्षेत्र के लिए 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति वहाँ के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगी। पदों का सृजन स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी उपलब्ध कराएगा।" उन्होंने आगे कहा "पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। हमारी सरकार 'हर घर स्वास्थ्य, हर व्यक्ति स्वस्थ' के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है। पिलखी क्षेत्र में यह निर्णय लोगों की लंबी प्रतीक्षा को समाप्त करेगा और निकट भविष्य में बेहतर चिकित्सा ढाँचे का लाभ मिलेगा।" मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा "सरकार का संकल्प स्पष्ट है–प्रदेश का कोई भी नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। घनसाली क्षेत्र की स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को चरणबद्ध तरीके से उन्नत किया जाएगा। आवश्यक पदों की तैनाती, भवन सुधार एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।" इस अवसर पर घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा संयोजक मण्डल से श्री संजीव आर्य, श्री विक्रम कपाल, श्री अनुग्रह लाल शाह, श्री अनुग्रह लाल शाह, श्री गोविन्द दिगारी, श्रीमती सुनीता पवार, श्रीमती कमला पंवार, श्री अनुग्रह कपाल व श्री अंकित नौडियाल उपस्थित रहे।

मीना ने की कांग्रेस की रैली में शामिल होने की अपील

रुद्रपुर। दिल्ली रैली को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष श्रीमती मीना शर्मा, सहित महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती ममता रानी, विभिन्न बस्तियों में जा जा कर रैली को सफल बनाने के लिए सभाएं कर रही हैं। जिसमे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं। इधर बुधवार को तीन पानी डैम, फुलसुन्गा में शिव इंक्लैव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर दिल्ली रैली में 14 दिसम्बर को चलने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस के बरिष्ठ नेता अनिल शर्मा, उमा सरकार, अरविंद सक्सेना, नरेश कुमार सागर, शालू शर्मा, महेंद्र यादव, किरण, सरोज, दीवान सिंह, सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मुख्य विकास अधिकारी ने किया विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी ने पूर्वान्ह 10 बजे विकास भवन स्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अर्थ एवं संख्या विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संजय सिंह, कनिष्ठ सहायक कु0 भावना राणा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी राजीव कुमार जायसवाल, डाटा एन्ट्री आपरेटर प्रमोद कुमार व कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के वरिष्ठ सहायक संतोष कुमार कमल, अनुसेवक नन्दा बल्लभ पाण्डे, महिला कल्याण विभाग के प्रशासनिक अधिकारी रजनीश पंत व महिला सशक्तिकरण विभाग के वाहन चालक जयनारायण अनुपस्थित पाये गये। मुख्य विकास अधिकारी ने

कर्मचारियों की अनुपस्थित को अत्यधिक गम्भीरता से लेते हुए अनुपस्थित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त अर्थ एवं संख्या विभाग की अपर सांख्यिकीय अधिकारी प्रीति चोपड़ा, अन्वेषक कम संगणक कु0 पूजा नयाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के सहायक कृषि अधिकारी वर्ग–1 कमल राणा भ्रमण पर होने पाये गये। उन्होने कर्मचारियों के भ्रमण में होने की पुष्टि के लिए सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष से सुस्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने विकस भवन स्थित समस्त कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रत्येक कार्य दिवस में समस्त अधिकारी/कर्मचारी पूर्वान्ह 10 बजे अपने–अपने कार्यालय में उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि भविष्य में कार्यालयों में कर्मचारियों की अनुपस्थिति हेतु सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों का उत्तरदायी माना जायेगा।

विभिन्न वार्डो में पेयजल लाइनें बिछाई

सितारगंज। जल संस्थान ने नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में पेयजल की लाइनें बिछाई गई हैं। जिससे आमजन को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। इसके साथ ही जल संस्थान ने नालियों से कनेक्ट जल संयोजन को ऊपर लगाने की अपील की हैं। जल संस्थान के जेई संजीव गोस्वामी ने बताया कि नगरीय क्षेत्र के मुख्य मार्गो में पेयजल लाइनें होने से आंतरिक गलियों में रहने वाले आमजन को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। जिसको देखते हुए नगरीय क्षेत्र के वार्ड तीन में सुनहरी मस्जिद के आसपास की गलियों में पेयजल लाइनें बिछाई गई हैं। उन्होंने जल संस्थान के उपभोक्ताओं से अपील की है, की नालियों से कनेक्ट पेयजल लाइनों को वहां से हटाकर ऊपर के हिस्से में लगाएं। जिससे नालियों का गंदला पानी पेयजल पाइप लाइन के माध्यम से नलों में न पहुंच सके।

आठ घरों में पकड़े विद्युत चोरी के मामले

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। विद्युत विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान ग्राम छत्तरपुर मेंआठ घरों में विद्युत चोरी के मामले पकड़कर भवन स्वामियों के विरूद्ध मुकदमें दर्ज करा दिये। जानकारी के अनुसार अन्नू अरोरा उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड के नेतृत्व में कुलदीप सिंह अवर अभियन्ता, सुखवन्त सिंह लाईन कर्मी, पुनीत कुमार सहायक अभियन्ता सतर्कता ने ग्राम छत्तरपुर में विद्युत चैकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रेमनाथ पुत्र राम आज्ञा, सुरेन्द्र पुत्र खलीफा, रामपाल पुत्र खलीफा, मोतीराम पुत्र सुरेश, सकलदीप पुत्र हरिकिशन, मनोज पुत्र केदार, अनुज पुत्र केदार व जवाहर पुत्र जंगली के भवनों में विद्युत चोरी के मामले सामने आये। टीम ने मौके पर केबल जब्त कर ली। विभाग द्वारा उक्त सभी भवन स्वामियों के विरूद्ध विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की श्रीमती शीतल भाटिया जी का एक बैनामा जो की श्री शिव कुमार पुत्र बाबू सिंह निवासी 6/179 के नाम से दिनांक 20.04.2007 बैनामा संख्या 1167 बही नंबर जिल्द पेज में तहसील किच्छा में दर्ज है कहीं गुम हो गया है यह सूचना गुम दस्तावेज के संबंध में दी जा रही है ताकि भविष्य में उक्त दस्तावेज उपयोग में ना लिए जाए यदि किसी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते है तो वो किसी प्रकार से मान्य नहीं होंगे।

शीतल भाटिया पत्नी सन्नी भाटिया, निवासी आवास विकास रूद्रपुर

जगदीश
कलर लैब
टंडन फोटो स्टूडियो
पासपोर्ट फोटो तुरन्त प्राप्त करें
जनरेटर सुविधा भी उपलब्ध है।
05944-246817

आम जनमानस को समान नागरिक संहिता के प्रति करें जागरूक

रुद्रपुर। पंकज कुमार उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी/नोडल अधिकारी (यूसीसी) उधम सिंह नगर द्वारा दिनांक 10.12.2025 को सचिव, वित्त विभाग/महानिबंधक यूसीसी द्वारा की गयी समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के क्रम में आज समस्त संबंधित अधिकारीगणो के साथ जनपद स्तर पर समान नागरिक संहिता की प्रगति की समीक्षा की गई एवं माह जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले यूसीसी दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के सम्बंध में समस्त संबंधितो को यथावश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही आम जनमानस को समान नागरिक संहिता के प्रति जागरूक करते हुए अधिक से अधिक मात्रा मैं पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रेरित किये जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में श्री मनीष बिष्ट, उपजिलाधिकारी रुद्रपुर, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी उधम सिंह नगर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उधमसिंह नगर, जिला आशा समन्वयक उधमसिंहनगर तथा जनपद के अन्य समस्त संबंधित अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपास्थि रहे।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)- 263148, ई-मेल:- eddkichha@gmail.com

विद्युत बाधित सूचना

विद्युत वितरण खण्ड किच्छा के अधीन सम्बन्धित 33/11 के0वी0 उपसंस्थान किच्छा में अनुबन्ध सं0 1351 एवं 1352/C (C&P-1)/41/2023-24 / Package K - RDSS-EDC RDR/ Rajshayama / Supply And Erection Date 14-08-2024 के तहत के परियोजना के अन्तर्गत कार्य होना प्रस्तावित है। सारणी अनुसार निम्नलिखित तिथि को विद्युत आपूर्ति पूर्णतः / आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि विभाग को सहयोग करने की कृपा करें व उक्त समयावधि में वैकल्पिक व्यवस्था भी करने का कष्ट करें तथा इन्वर्टर व जनरेटर को चलाते समय ग्रिड लाईन से अलग करके ही चलाये जिससे बैंक फिडिंग के कारण किसी भी अप्रिय घटना से बचाव हो सके।

क्रम0 सं.	उपसंस्थान का नाम	प्रभावित पोषक	प्रभावित क्षेत्र	तिथि	समय
1	33/11 के.वी. उपसंस्थान किच्छा	33 के.वी. एस.आर.होण्डा	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, महिन्द्रा सी0आई0ई0, साई बाबा उद्योग व स्वातिक आहार	14.12.2025	प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

Customer Care Toll Free No - 1912
Pay Electricity Bill online 24x7 from www.upcl.org (राष्ट्र हित में बिजली बचायें)

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 5039/वि.वि.ख. (कि.)/ दिनांक 11.12.2025

किसान मंच ने कुसुम लता बौड़ाई को बनाया प्रदेश प्रवक्ता

देहरादून। किसान मंच ने राज्य में महिला किसानों से जुड़े मुद्दों को मजबूती देने के उद्देश्य से कुसुम लता बौड़ाई को प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड नियुक्त किया है। संगठन का कहना है कि पर्वतीय कृषि में महिलाओं की रीढ़ जैसी भूमिका को पहचान देना समय की मांग है और इसी दिशा में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुसुम लता बौड़ाई लंबे समय से सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रही हैं और विभिन्न जन आंदोलनों में उनकी निरंतर भागीदारी उन्हें ग्रामीण समाज के बीच मजबूत पहचान दिलाती है। पहाड़ के एक साधारण गांव से निकलकर उन्होंने शहर में अपनी शिक्षा पूरी की और अब पुनः गांव लौटकर समुदाय और किसानों के बीच काम कर रही हैं। संगठन का मानना है कि उनका यह अनुभव उन्हें महिला किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझने और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करेगा। किसान मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि मंच पूर्व प्रधानमंत्री स्व. वी.पी. सिंह की किसान–

केंद्रित विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राज्य के किसानों के अधिकारों और न्याय के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिला किसानों की आवाज अक्सर नीतिगत चर्चाओं में पीछे रह जाती है, जबकि पहाड़ की खेती का सबसे बड़ा भार आज भी महिलाओं के कंधों पर है। नव नियुक्त प्रवक्ता कुसुम लता बौड़ाई ने अपनी नई जिम्मेदारी के लिए संगठन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे दुर्गम क्षेत्रों की महिला कृषकों की वास्तविक चुनौतियों चाहे वह बाजार तक पहुंच हो, तकनीक की कमी हो या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समस्याख्र इन सभी को शासन स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि "पहाड़ की खेती महिलाओं की मेहनत और धैर्य पर टिकी है, अब समय है कि उनकी आवाज भी नीतिगत फैसलों में स्पष्ट रूप से सुनी जाए।" संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कुसुम लता बौड़ाई की सक्रियता और सामाजिक जुड़ाव से किसान मंच के काम को नई दिशा एवं मजबूती मिलेगी। साथ ही महिला किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रदेश में अधिक प्रभाव और पहचान प्राप्त होगी।

धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं पीआरडी जवान : धामी

सीएम ने की पी.आर.डी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की घोषणा

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को ननूरखेड़ा, देहरादून स्थित निदेशालय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल परिसर में प्रान्तीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने दिवंगत पीआरडी स्वयंसेवकों के आश्रितों को सहायता राशि एवं पीआरडी जवानों के बच्चों को छात्रवृत्ति के चेक भी प्रदान किए।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कि की पी.आर.डी जवानों के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। पीआरडी जवानों को भी अब ड्यूटी के दौरान चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में उपचार के दौरान ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उन्हें अधिकतम छह माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ग्राम अस्थल रायपुर में खेल मैदान का निर्माण भी किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पी.आर.डी जवान, धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ प्रदेश में सुरक्षा और जनसेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पीआरडी जवान, प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, सुरक्षा व्यवस्था, लिपिकीय कार्यों और विभिन्न विभागीय का दायित्वों, प्राकृतिक आपदाओं में चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में कार्य कर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। चार धाम यात्रा के दौरान भी जवानों ने धैर्य, संवेदनशीलता और सजगता के साथ लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा कराने में सहयोग किया।मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य गठन के समय पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था। अब उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए उसे 650 रुपये प्रतिदिन किया गया है। पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार ने मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की है।मुख्यमंत्री ने कहा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपये का एकमुश्त सेवा-भत्ता भी प्रदान किया है। साम्प्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख किया गया है। पीआरडी जवान की अति-संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75 हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की है। सामान्य ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की दशा में मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि साम्प्रदायिक दंगों और अति-संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए भी संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। जवानों की सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण का सम्मान करते हुए हमनें वर्ष 2023 में मृत एवं अपंग जवानों के आश्रितों को पीआरडी जवान के रूप में पंजीकृत करना प्रारंभ किया था। जिसके पश्चात अब तक पंजीकृत 190 आश्रितों में से 133 आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माह 149 पंजीकृत आश्रितों को विभागीय अर्द्ध सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिससे वे अपने कौशल में वृद्धि कर सकेंगे और भविष्य में पीआरडी सेवा के विभिन्न दायित्वों को और अधिक दक्षता और तत्परता के साथ निभाने में सक्षम होंगे। कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी जवान, हर स्थिति में प्रदेश की सेवा करते हैं। चुनावों , पर्व त्यौहारों, आपदा से लेकर आम दिनों तक पीआरडी जवान हमेशा आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के हितों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 2022 से इस स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। आज हमारे 7500 से अधिक पीआरडी जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर निदेशक युवा कल्याण श्री राकेश डिमरी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

राज्य स्तरीय महिला वॉलीबाल चैंपियनशिप का डीएम ने किया शुभारंभ

रूद्रपुर(उद संवाददाता)। उत्तराखण्ड वॉलीबाल एसोसिएशन एवं खेल विभाग के तत्वाधान में रूद्रपुर मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला वॉलीबाल चौंपियनशिप-2025 का जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, अध्यक्ष उत्तराखण्ड वॉलीबाल एसोसिएशन कमलेन्द्र सिंह धानक, महासचिव उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन डॉ0 डीके सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने प्रतियोगिता के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आगे चलकर यही खिलाड़ी प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ी खेल भावना व अनुशासन के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। उन्होंने कहा आज खेलों में युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। खेलों से युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग हैं। खेलों से न सिर्फ शारीरिक विकास होता है बल्कि मन मस्तिक भी स्वस्थ रहता होता है। उन्होने कहा सभी खिलाड़ी टीम भावना के साथ खेले व अपना शतप्रतिशत देकर टीम को जिताये। उन्होने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना व बधाई दी। इस अवसर पर महासचिव ओलम्पिक एसोसिएशन डॉ0 डीके सिंह व जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी व सभी खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील भी की। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तरीय वॉलीबाल चौम्पियनशिप महिला 11 व 12 दिसम्बर एवं पुरूष चौम्पियनशीप 13 व 14 दिसम्बर को आयोजित होगी। उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय महिला वॉलीबाल चौम्पियनशिप में जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार व देहरादून की कुल राज्य की 10 टीमों के लगभग 130 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही है। कार्यक्रम में महासचिव उत्तराखण्ड साईकिलिंग एसोसिएशन दिवेश पाण्डे, जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत सहित कोच, रेफरी, खिलाडीघआदि मौजूद थे।

SAHAS Homeo
साहस होम्यो मेडिकल स्टोर एवं क्लीनिक
जर्मन तथा सभी प्रकार के होम्योपैथिक व बायोकैमिक दवाईयों के विक्रेता
डॉ. यश पाण्डेय

होम्योपैथिक फिजिशियन
बी.एच.एम.एस., जयपुर
चर्म रोग | गुर्दा रोग | पेट रोग
गुदा रोग | लिवर सम्बन्धि रोग
अन्य रोग • स्पान्डीलाईटिस • श्वास रोग • मोटापा • दमा • प्रोस्टेट • माइग्रेन • टान्सिल • एलर्जी • ब्रोनकाइटिस
बच्चों के रोग • पेट का दर्द • अपच • कान में संक्रमण / दर्द • खांसी • जुकाम • निमोनिया • बुखार • दांत निकलना
साहस होम्यो क्लीनिक
निकट गुरुद्वारा, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी
मो. 9456727473, 9410514531 शनिवार अवकाश

राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कल

रूद्रपुर। मा0 उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर द्वारा जनपद में 13 दिसम्बर 2025 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक रूद्रपुर स्थित जिला न्यायालय सहित वाह्य स्थित दीवानी न्यायालयों काशीपुर, खटीमा, बाजपुर, जसपुर, सितारगंज एवं किच्छा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेन्द्र कुमार सागर ने बताया कि 13 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन के वादों का निस्तारण किया जाएगा जैसे- भरण पोषण, धन वसूली, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, अपराधिक शमनीय व सिविल मामले इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लम्बित शमनीय प्रकृतिक के आपराधिक वाद/अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम विवाद, विद्युत व जल कर बिल संबंधित, वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, भुगतान व भत्तों से सम्बन्धित सर्विस के मामले, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व वाद, मोटर वाहन अधिनियम के शमनीय अपराधों के चालान, सिविल मामले (किरायेदारी, सुखाधिकार, व्यादेश) का निस्तारण किया जाएगा। उन्होने अपील करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति अपने वादों/मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करवाना चाहते हैं वे सम्बन्धित न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादों को नियत करवा सकते है या जिला न्यायालय परिसर में स्थित एडीआर केन्द्र रूदुपर में स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए नालसा हैल्प लाइन नं0-15100, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर एडीआर केन्द्र रूद्रपुर के हैल्प डैस्क नं0-9411531449, ई-मेल- dlsausnagar@gmail-com] फोन नं0-05944-250682 पर सम्पर्क कर सकते है।

छात्र ने घर में जहर खाकर दे दी जान

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। लालकुआं कोतवाली के बिंदुखत्ता क्षेत्र में बुधवार को 16 वर्षीय छात्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में सल्फास खाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। गंभीर हालत में उपचार के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से बागेश्वर जिले के समा गांव निवासी केशर सिंह परिवार के साथ कई वर्षों से बिंदुखत्ता, कालिका मंदिर के पास रहते हैं। पिता दिल्ली में निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि मां विमला स्थानीय निजी स्कूल में काम करती हैं। इसी स्कूल में उनका पुत्र विक्रम 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बुधवार सुबह विक्रम ने छोटी बहन के साथ नाश्ता किया और दोस्तों संग घर के पास मोबाइल गेम खेलने गया। कुछ देर बाद वह घर लौटा और अज्ञात कारणों से सल्फास खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद छोटी बहन ने मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। परिजन उपचार के लिए पहले उसे नजदीकी निजी अस्पताल ले गए। जहां से हालत गंभीर बताकर रेफर कर दिया गया। शाम करीब 6.50 बजे उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुधवार रात 11.45 बजे उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मेडिकल चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि परिजनों से पूछताछ कर घटना की जांच की जा रही है।

एएनएम को प्रशिक्षण के साथ बांटी टीकाकरण सामग्री

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. के.के. अग्रवाल की अध्यक्षता में नियमित टीकाकरण की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें विकास खण्ड रुद्रपुर की समस्त ए.एन.एम. को वीएचएसएनडी बैग, वेक्सिनेशन ट्रे, मैग्निफाइंग ग्लास, डायरी 2026, पेन, ईम्युनिजेशन पॉकेट चार्टस, हब कटर, ग्लूकोमीटर, 4 टाइप वैक्सीन करियर स्टिकर, बीएचए सएनडी बैनर, मीजल्स रुबेला बैनर टीकाकरण से सम्बन्धित सामाग्री को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वितरित की गई। नियमित टीकाकरण, यू-विन, आर.सी.एच.,एच.एम.आई.एस. ,डाटा, प्रबन्धन, माईक्रो प्लानिंग, ए.ई.एफ. आई, वी.पी.डी. सर्विलांस का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सर्विलांस मेडिकल आफिसर डा. मीनाक्षी सुमन ने जिला स्तर पर टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की पहचान, वर्गीकरण, रिर्पोटिंग एवं निगरानी प्रणाली संबंधी जरूरी सुझाव दिये। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. राजेश आर्या द्वारा बताया गया कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद में निवासरत सभी समुदायों को टीकाकरण की सेवायें देकर उन्हें बीमारियों से बचाया जाना है। साथ ही सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये कि टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं की रिर्पोटिंग तुरंत जिला मुख्यालय में की जाए जिससे ए.ई.एफ.आई. सर्विलांस को और अधिक प्रभावी किया जा सके। इसी के साथ प्रदीप महर, सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं प्रदीप पाठक, वी.सी.सी.एम. के द्वारा यू.-विन पोर्टल पर एन्ट्री करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान की गई। साथ ही चाँद मियां जिला डाटा मैनेजर द्वारा आर.सी.एच. एवं एच.आई.एम.एस. की आनलाईन एंट्री की करने एवं डाटा प्रबन्धन की प्रशिक्षण प्रदान की गई।

विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया कुलपति का पुतला दहन

रामनगर। गुरुवार को पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं कुलपति तथा कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया छात्र संघ उपाध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा फॉर्म का विलंब शुल्क दुगना करने के खिलाफ पूर्व में परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में धरना दिया गया था उनका आरोप है

कि इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षा प्रवेश फार्म की बड़ी हुई फीस को पूर्व की भांति निर्धारित करने का आश्वासन दिया गया था उन्होंने आरोप लगाकर बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया जिस कारण कई छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज से जहां एक और छात्र छात्राएं आते हैं तुम्हें कई विद्यार्थी गरीब भी हैं ऐसे में इस प्रकार का शुल्क लिया जाना अच्छा छात्रों के लिए न्याय संगत नहीं है उन्होंने कहा कि यदि इस बड़े हुए शुल्कों को रद्द कर शीघ्र पूर्ण की भांति फीस निर्धारित नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

न्यायाधीशों व अधिवक्ताओं ने किया रक्तदान

नैनीताल (उद संवाददाता)। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर में राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने भाग लेते हुए तीस यूनिट से अधिक रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घघाटन करते हुवे उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने आयोजित रक्तदान शिविर को न्याय व मानवता का सच्चा उत्सव बताया। जिला जज हरीश गोयल सहित अनेक न्यायिक अधिकारियों एवंअधिवक्ताओं ने रक्तदान कर समाज सेवा की मजबूत भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने रक्तदान को लेकर सभी को प्रेरित किया। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, सालसा सचिव प्रदीपमणि त्रिपाठी, डीएलएसए सचिव पारुल थपलियाल, द्वितीय अपर जिला जज कुलदीप शर्मा, सिविल जज हर्ष यादव, सीजेएम रवि प्रकाश, एसीजेएम रवि रंजन, बार एसोसिएशन अध्यक्ष भगवत प्रसाद, सचिव दीपक रुवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष मोहन जोशी, नीरज साह, हरिशंकर कंसल बहादुर पाल, ओंकार गोस्वामी, उपाध्यक्ष शंकर चौहान, गोपाल सिंह कपकोटी, प्रमोद बहुगुणा, बी.के. सांगुड़ी, गिरीश खोलिया, डीजीसी सुशील कुमार शर्मा, राजेश चंदोला, राम सिंह रौतेला, भुवन जोशी, सुभाष जोशी, शिवांशु जोशी, गौरव कुमार, नीलेश भट्ट, दिग्विजय सिंह बिष्ट, रवि कुमार, निर्मल कुमार, दीपक दत्त पांडेय, तरुण चंद्रा, राजेन्द्र भैसोड़ा, नीरज गोस्वामी, प्रमोद कुमार, प्रदीप कुमार सहित अनेक अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 17 को किसान दिवस मनाया जायेगा

रूद्रपुर। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में किसानो को विधिक समस्याओं/मुद्दो के समाधान और उन्हे तकनीकी एवं वैज्ञानिक रूप से सक्षम एवं जागरूक बनाने हेतु जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में 17 दिसम्बर बुधवार को किसान दिवस मनाया जायेगा। किसान दिवस के साथ ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील खटीमा में 16 दिसम्बर को आयोजित होने वाला तहसील दिवस तथा जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित होने वाले तहसील दिवस 16 दिसम्बर के स्थान पर 17 दिसम्बर को किसान दिवस के साथ ही ब्लॉक मुख्यालय में संयुक्त रूप से आयोजित किये जायेगे। जिलाधिकारी ने तहसील दिवस/किसान दिवस के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। ब्लॉक मुख्यालय खटीमा हेतु स्वयं जिलाधिकारी, काशीपुर हेतु मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रपुर हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन, बाजपुर हेतु अपर जिलाधिकारी वि0/रा0, जसपुर हेतु उप जिलाधिकारी काशीपुर, गदरपुर हेतु उप जिलाधिकारी गदरपुर, सितारगंज व नानकमत्ता हेतु उप जिलाधिकारी सितारगंज व किच्छा तहसील हेतु उप जिलाधिकारी किच्छा नोडल अधिकारी रहेगें। उन्होने बताया कि उक्त अधिकारियों के अतिरिक्त तहसील एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले किसान दिवस व तहसील दिवस में प्रतिभाग करते हुए अपने-अपने ब्लॉक में उपस्थित रहेगें तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी कार्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने हेतु ब्लॉक खटीमा में उपस्थित रहेगें।

सर्दियों में बढ़ा मानव वन्यजीव संघर्ष : कॉर्बेट प्रशासन ने ग्रामीणों को जंगल जाने से रोका

रामनगर। सर्दियों के आते ही उत्तराखंड के जंगलों में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाघ, तेंदुए और अन्य जंगली जानवर सर्द मौसम में अधिक आक्रामक हो जाते हैं। इसी को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने ग्रामीणों से जंगलों में लकड़ी, चारा या अन्य जरूरतों के लिए अकेले न जाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस समय जंगलों में गतिविधियां कम से कम रखें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें।जंगलों में इस वक्त मेटिंग पीरियड भी होता है और ठंड में जानवरों के व्यवहार में बदलाव आने के कारण बाघ और तेंदुए मानव बस्तियों के करीब तक आ सकते हैं। ऐसे में किसी भी अप्रत्याशित घटना की आशंका बढ़ जाती है। कॉर्बेट क्षेत्र के अधिकारी लगातार गांवों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि जीवन किसी भी जोखिम से बढ़कर है और कुछ समय तक जंगलों में प्रवेश से परहेज करना ही सुरक्षित विकल्प है।लेकिन इसके बावजूद कई ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगलों की ओर जा रहे हैं। गरीब परिवारों के पास खाना पकाने और सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जुटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। इसी मजबूरी के चलते लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जंगलों में प्रवेश कर रहे हैं। कई गांवों में महिलाओं और बुजुर्गों के अकेले जंगल जाने की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है।कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है। स्थानीय पुलिस, वन विभाग और ग्राम पंचायतें मिलकर ग्रामीणों को सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही, टीमों को हाई-अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक रूप से जंगलों की ओर न जाएं। सर्दियों का यह समय वन्यजीवों के लिए संवेदनशील होता है, और थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

शहीदी दिवस पर निकली यात्रा का किया स्वागत

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। श्री गुरू तेग बहादुर साहिब के 350 वें शहीदी पर्व को समर्पित निकाली जा रही यात्रा का गत दोपहर नगर में पहुंचने पर गुरूद्वारा श्री गुरुसिंह सभा गोल मार्केट के समक्ष गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी व स्त्री सत्संग सभा द्वारा पुष्प वर्षा व जो बोले सो निहाल सतश्री अकाल के जयघोषों से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गुरू की महिमा के गुणगान से सारा वातावरण गुंजायमान हो उठा। उपस्थित संगत ने गुरू जी का आर्शीवाद लिया और देश समाज की खुशहाली के लिए अरदास की। स्त्री सत्संग की प्रधान परमजीत कौर पम्मी ने बताया कि यह ऐतिहासिक यात्रा श्री गुरू तेग बहादुर जी की अमर शहादत को याद करने तथा उनके बलिदान के सन्देश को संगत तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। अंत में गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जोगेन्दर सिंह व स्त्री सत्संग सभा की प्रधान परमजीत कौर पम्मी ने सारी संगत का धन्यवाद किया व लंगर प्रसाद की सेवा की। इस दौरान जीत सिंह चाचू, अजमेर सिंह, हरजीत सिंह विरदी, नरेश कुमार सेठ, मान सिंह ग्रोवर, जगदेव सिंह, गुरमीत सिंह बठला, सतवीत सिंह, महेन्द्र सिंह असीजा, कंवल सिंह बठला, संदीप बठला सहित भारी संख्या में संगत मौजूद रही।

अतिक्रमण पर चेतावनी के साथ महापौर ने चालान में दी रियायत

रुद्रपुर। नगर निगम की हालिया अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई में बाजार क्षेत्र के कई व्यापारियों पर लगाए गए चालान में व्यापारियों को राहत मिली हैं। गुरुवार को देवभूमि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सुनील ठुकराल के नेतृत्व में मिले व्यापारियों की गुहार के बाद महापौर विकास शर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सहायक नगर आयुक्त राजू नवियाल को चालान की धनराशि में रियायत देने के निर्देश जारी किए। बता दें पिछले दिनों महापौर के निर्देश पर बाजार में सड़क पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। मनमानी करने वाले कई व्यापारियों के पाँच से दस हजार रुपये तक के चालान काटे गये थे। कार्रवाई के बाद बाजार में व्यवस्था तो सुधरी, लेकिन भारी चालान को लेकर व्यापारी चिंतित थे। नगर निगम में भेंट के दौरान व्यापारियों ने महापौर के समक्ष चालान माफ करने का आग्रह किया। साथ ही बाजार क्षेत्र की समस्याओं को भी विस्तार से रखा। इसमें जगह-जगह डस्टबिन लगाने, बिजली की तारों को भूमिगत करने, नालियों के निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग मुख्य रूप से शामिल रही। महापौर ने इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। महापौर ने व्यापारियों को फिलहाल चालान में रियायत देने के साथ ही व्यापारियों को कड़े शब्दों में चेताया कि यह अंतिम अवसर है। आगे से यदि किसी दुकान का सामान नाली से बाहर पाया गया, तो चालान के साथ-साथ सामान भी जब्त किया जाएगा। व्यापारियों ने भी आश्वस्त किया कि भविष्य में कोई भी व्यापारी सड़क पर अतिक्रमण नहीं करेगा और उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करें। महापौर ने बताया कि मुख्य बाजार को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर नगर निगम तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वीर हकीकत राय मार्ग को हाईटेक सुविधाओं से लैस बनाने का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, और जल्द ही यह शहर का सबसे आकर्षक मार्ग बनेगा। इसी तरह शहर की अन्य प्रमुख सड़कों को भी विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र में जहां नाली और फुटपाथ बनना है उसके लिए बजट स्वीकृत किया जा चुका है। इसी माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रुद्रपुर आगमन के दौरान इन विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया जायेगा। महापौर के साथ हुई बैठक में अध्यक्ष सुनील ठुकराल सहित अन्य व्यापारियों ने चालानों में रियायत देने और अन्य विकास कार्यों के प्रति आश्वासन पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान पार्षद चिराग कालरा, अमित अरोरा, सन्नी, केवल बत्रा, सुभाष बत्रा, जौम्बी भल्ला, शिवम अनेजा, अक्षित अनेजा, बल्देव ग्रोवर, राहुल छाबड़ा आदि मौजूद रहे।

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

बाल्यावस्था में सोशल मीडिया

आधुनिक तकनीकी युग में इंटरनेट ने दुनिया को अभूतपूर्व रूप से जोड़ने का कार्य किया है। सूचनाओं, विचारों और अनुभवों का वैश्विक आदान-प्रदान इतना सहज कभी नहीं रहा। निस्संदेह, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण भौगोलिक दूरियाँ सिमट गई हैं, लेकिन इसी के समानांतर एक विडंबना भी उभरकर सामने आई हैख्र ''वर्चुअल निकटता के बीच वास्तविक दुनिया के रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं।''आज की पीढ़ी खासकर बच्चे, जो मानसिक निर्माण तथा सामाजिक विकास के संवेदनशील दौर में होते हैं, डिजिटल संबंधों के विस्तार के चलते वास्तविक सामाजिकता से दूर होते जा रहे हैं। यह तथ्य अब किसी से छिपा नहीं है कि मोहल्ले या स्कूल के जिन बच्चों में पहले सहज संवाद और खेलकूद का वातावरण होता था, वही बच्चे आज सोशल मीडिया या किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर तो मित्र बने हुए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में शायद ही कभी मिलते हों । आभासी रिश्तों का यह विस्तार बच्चों को डिजिटल दुनिया में तो सक्रिय बनाए रखता है, लेकिन ''यथार्थ में वे पहले से अधिक अकेले, संकोची और भावनात्मक रूप से असंतुलित होते जा रहे हैं।''धीरे-धीरे यह अकेलापन बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के उनके मन में उतरता है और उन्हें मनोवैज्ञानिक दबाव, अवसाद और आत्महत्यात्मक प्रवृत्तियों की ओर धकेल सकता है विभिन्न देशों से इस तरह की घटनाओं की लगातार खबरें आती रही हैं जहाँ किसी एप, गेम या चुनौती (चौलेंज) में उलझे बच्चे मानसिक शोषण या दबाव का शिकार होकर चरम कदम उठाते दिखाई देते हैं। यह स्थितियाँ समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन चुकी हैं। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते आए हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चों की अति-निर्भरता उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैख्र इन्हीं चिंताओं के आधार पर दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने के प्रयास जारी रहे हैं।इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश की सरकार ने ''सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध'' लागू कर दिया है। कुछ संदेश सेवा (मैसेजिंग) और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इसका अपवाद बनाया गया है, लेकिन व्यापक रूप से यह कड़ा फैसला बच्चों को डिजिटल जंजाल से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। हालाँकि यह निर्णय स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज के बच्चे तकनीकी रूप से अत्यंत चतुर हैं। वे कई बार माता-पिता की निगरानी से बचने के तरीके खोज लेते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या यह प्रतिबंध वास्तव में सोशल मीडिया के जाल से बच्चों को बचा पाएगा। यदि सोशल मीडिया कंपनियों को बच्चों की आयु की पुष्टि के लिए किसी दस्तावेज या पहचान की मांग करनी पड़ेगी, तो इसके साथ नए सवाल खड़े होंगे। क्या बच्चों की संवेदनशील पहचान सुरक्षित रहेगी? क्या डेटा का दुरुपयोग हो सकता है? क्या इससे नए प्रकार की ऑनलाइन निगरानी (सर्विलांस) का खतरा बढ़ेगा? क्या यह बच्चों के डिजिटल अधिकारों और निजता को प्रभावित करेगा? इसलिए नियमन के साथ-साथ कड़े डेटा-सुरक्षा प्रावधानों की भी आवश्यकता है। बच्चों को सोशल मीडिया के खतरों से बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान केवल प्रतिबंध नहीं हो सकता। इसके लिए समाज, स्कूल, माता-पिता और सरकार को मिलकर व्यापक रणनीति अपनानी होगी। सोशल मीडिया आधुनिक जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि है।ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू प्रतिबंध इस दिशा में एक साहसी कदम है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि माता-पिता, समाज और तकनीकी कंपनियाँ इसे कितना गंभीरता से अपनाते हैं।

राज्यपाल ने किया नि:शुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का उद्घाटन

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने गुरूवार को गांधी रोड, देहरादून में हर्षल फाउंडेशन द्वारा आयोजित नि:शुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का उद्घाटन किया। दो दिवसीय इस शिविर में उन्होंने दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों से संवाद उन्होंने कहा कि यह मानवता की सेवा का सच्चा उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा अब तक दस हजार से अधिक दिव्यांगजन को लाभान्वित किया गया है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगजन को दया नहीं, बल्कि अवसर और सम्मान की लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक और एआई के उपयोग से दिव्यांगजनों के जीवन को और अधिक सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। दो दिवसीय शिविर में कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर, बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, वॉकर, स्टिक, श्रवण-यंत्र, रही अन्य संस्थाओं, चिकित्सा टीम, स्वयंसेवकों तथा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने भी फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की प्रशंसा करते हुए

कर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल की उपस्थिति में अनेक लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हर्षल फाउंडेशन द्वारा वर्षों से संचालित यह शिविर मानवीय संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। आवश्यकता है। यदि उन्हें उचित सहयोग, आधुनिक तकनीक एवं सकारात्मक वातावरण मिले, तो वे प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में भारत की नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की टी-20 विश्व कप विजेता तथा पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये उदाहरण साबित करते हैं कि दिव्यांगजन समाज के विशेष चश्मे सहित अनेक सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, फिजियोथेरेपी, चिकित्सा परामर्श एवं बीमारियों की जाँच तथा विशेषज्ञ सलाह की व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांगजन के लिए कौशल विकास और रोजगार सहायता से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। राज्यपाल ने इस शिविर में सहयोग कर कहा कि दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और अपनी मेहनत एवं कौशल से स्वयं को सक्षम सिद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविर समाज में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करते हैं। शिविर में फाउंडेशन की अध्यक्ष रमा गोयल, सचिव श्री घनश्याम अग्रवाल, श्री राजेश टंडन, ब्रिगेडियर के जी बहल, डॉ. एस फारूख सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

आईएमए से पास आउट हो रहे कैडेट्स ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से लोक भवन में इंडियन मिलिट्री अकादमी (आईएमए) से पास आउट हो रहे 18 ऑफिसर कैडेट्स ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने सभी कैडेट्स को पासिंग आउट पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल एवं सफल सैन्य करियर की शुभकामनाएं दीं। ये सभी ऑफिसर कैडेट्स अब असम रेजीमेंट में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन कैडेट्स में से 03 ने सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब से शिक्षा प्राप्त की है। राज्यपाल ने विशेष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं भी सैनिक स्कूल कपूरथला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है और भारतीय सेना में अपनी गौरवशाली सेवाएँ असम रेजीमेंट में दी हैं। राज्यपाल ने कैडेट्स से कहा कि आप सभी देश की सेवा के लिए एक सम्मानित और

उत्तरदायित्वपूर्ण पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय सेना का हिस्सा बनकर आप राष्ट्र की सुरक्षा और अनुशासन की संस्कृति को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। राज्यपाल ने कैडेट्स से कहा कि उनके कार्यों में उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता झलकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा को सदैव उत्तम बनाए रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और दीर्घकालिक लक्ष्यों को दृष्टि में रखकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें। राज्यपाल ने भविष्य के लिए सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे भारतीय सेना की परंपराओं, गौरव और मूल्यों का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करेंगे।

उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग

आपदा एवं महामारी प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों को नई मजबूती प्रदान करेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

देहरादून। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM&ABHIM) के तहत केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंजूरी देने के बाद राज्य में स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निरंतर मार्गदर्शन में भ्म्ब की स्थापना का कार्य देहरादून स्थित महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिसर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में बन रहे निर्माणाधीन हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का निरीक्षण किया। टीम ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टमटा से भेंट की और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचना और डिजाइन पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद टीम ने नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह के साथ निर्माण स्थल का दौरा किया और केंद्र की तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी एवं व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना की। इस निरीक्षण प्रक्रिया ने न केवल परियोजना की विश्वसनीयता को मजबूत किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर HEOC को एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार की टीम में डॉ. सैयद जुल्फेकार अहमद, क्षेत्रीय निदेशक, आरओएचएफडब्ल्यू, लखनऊ, डॉ. निश्चय केशरी, चिकित्सा अधिकारी, आरओएचएफडब्ल्यू, लखनऊ, श्री आशिष, परामर्शदाता, श्री हेमंत नेगी मौजूद रहे तथा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की तरफ से HEOC नोडल अधिकारी डॉ पंकज सिंह तथा डॉक्टर सुजाता सिंह उपस्थित रहे। **भारत सरकार की टीम का निरीक्षण, गुणवत्ता पर संतुष्टि :** स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के निर्माण कार्य का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी निर्धारित गति से प्रगति पर है। उम्मीद है कि यह केंद्र जनवरी 2026 के अंत तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे औपचारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस केंद्र के संचालन को लेकर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपात प्रतिक्रिया से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सरकार का

स्पष्ट उद्देश्य है कि केंद्र के शुरू होते ही यह अत्याधुनिक क्षमता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (HEOC) की स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी। इस केंद्र के निर्माण का आधा कार्य पूरा हो चुका है। इस केंद्र के जनवरी 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है तत्पश्चात यह केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा । यह केंद्र भविष्य में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुख्य आधार बनने जा रहा है और आपदा एवं महामारी प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों को नई मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि HEOC की स्थापना से उत्तराखंड स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। यह केंद्र न केवल आपदाओं के समय तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य संबंधी निगरानी, डेटा विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा। इससे जिलों के बीच समन्वय बेहतर होगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता व गति आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य क्षेत्र लगातार शीर्ष पर रहा है और HEOC परियोजना इस प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। राज्य सरकार का विश्वास है कि केंद्र के पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाने पर उत्तराखंड न केवल अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी स्थापित करेगा। यह केंद्र उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई ऊर्जा, नई मजबूती और नई दिशा प्रदान करेगा, यही राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है। आपदाओं और महामारियों पर त्वरित प्रतिक्रिया का केंद्र बनेगा HEOC स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि भ्म्ब की स्थापना से राज्य को स्वास्थ्य आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। केंद्र स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को हर समय मजबूत रखेगा और संभावित खतरों की समय पर पहचान कर उचित कार्रवाई को संभव बनाएगा। यह केंद्र कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियों के दौरान हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक निगरानी तंत्र से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे किसी भी महामारी का प्रारंभिक चरण में पता लगाकर नियंत्रण किया जा सके। धराली जैसी आपदा स्थितियों में राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को भी यह केंद्र कई गुना बढ़ा देगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि HEOC न केवल एक भवन या संरचना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होगा। **राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने का प्रयास :** स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि देशभर में HEOC केंद्रों की स्थापना केंद्र सरकार की उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए देश को तैयार करना शामिल है। यह केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने और आपदा एवं महामारी प्रबंधन में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि पहाड़ी भूगोल, प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता और भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यहां स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भ्म्ब की स्थापना इस दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम है, जो आने वाले वर्षों में राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगा।

कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए प्रभारी

एक माह के भीतर 11733 बूथों पर तैनात करेगी बीएलए

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देश पर पार्टी कार्यक्रमों व संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रभारी बूथ कमेटियों का गठन के साथ ही एसआईआर प्रक्रिया में बीएलए बनाए जाने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। प्रभारियों को 2027 विस चुनाव के लिए ग्राम कांग्रेस, बाजार कांग्रेस, वार्ड कांग्रेस,मोहल्ला कांग्रेस और न्याय पंचायत कांग्रेस कमेटियों के गठन करने के निर्देश दिए गए। आगामी एक माह में राज्य के सभी 11733 बूथों पर बीएलए की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पुरोला में विजयपाल रावत एवं जोत सिंह रावत, यमुनोत्री में कनकपाल परमार, दीवान सिंह असवाल व अनुज रावत, गंगोत्री में शांति प्रसाद भट्ट, सरोज शाह, महावीर रावत, बदरीनाथ में चंद्रशेखर पल्लव, दिनेश रावत, थराली में हरीश चौहान, गुलाब सिंह बिष्ट, कमल रावत, कर्णप्रयाग में ईश्वर सिंह बिष्ट, संदीप कुमार पटवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। केदारनाथ में प्रकाश रावत, अंकुर रौथाण, रुद्रप्रयाग में अजय किशोर भंडारी व राकेश सिंह बिष्ट, घनसाली में देवेंद्र नौडियाल, गंभीर सिंह जयाड़ा, कृष्ण स्वरूप बडोनी, देवप्रयाग में विरेंद्र सिंह कंडारी, राकेश गुसाईं व विरेंद्र बुटोला, नरेंद्रनगर में श्याम लाल आर्य, विरेंद्र राणा, प्रतापनगर में शक्ति प्रसाद जोशी, मुन्नी बिष्ट, टिहरी में नरेंद्र सिंह राणा, भरत सिंह बुटोला, धनोल्टी में कुलदीप पंवार, अमित गुप्ता, जबर सिंह पंवार, विकासनगर में सलीम, सुरेंद्र सिंह, सहसपुर जितेंद्र रावत, गौतम डोगरा, संजय कुमार को नियुक्त किया गया। वहीं धर्मपुर में विजय प्रताप मल, जगदीश धीमान, अखिलेश उनियाल, रायपुर में नीनू सहगल, राजकुमार जयसवाल, जितेंद्र बिष्ट, राजपुर रोड में विपुल नौटियाल, दिनेश कौशल, डिम्पल सिंह, देहरादून कैंट में याकूब सिद्दिकी, ललित भद्री एवं नवनीत कुकरेती, मसूरी में अमेन्द्र बिष्ट एवं यशपाल चौहान, डोईवाला में धीरज नौटियाल बॉबी, डॉ. के.एस. राणा एवं सोहन लाल रतूड़ी, ऋषिकेश राजेन्द्र सिंह राणा, मनोज नौटियाल एवं संदीप चमोली, हरिद्वार में महेश प्रताप राणा एवं

वरुण वालियान, भेल रानीपुर में अनिल कुमार भास्कर, अजमोद कुमार चौहान, रवीश भटीजा को चुना गया। ज्वालापुर में सचिन चौधरी, हिमांशु बहुगुणा, भगवानपुर में विकास त्यागी, मुल्कीराज सैनी, झबरेड़ा में संजीव प्रधान, प्रधुम्न अग्रवाल, पंकज सोलंकी, पिरान कलियर में नासिर परवेज, वीरेंद्र सिंह, रुड़की में तेलु राम प्रधान, जतिन हांडा, रूप चौधरी, खानपुर में आशीष सैनी, चौधरी अरुण कुमार, सुधीर शांडिल्य, मैंगलोर में जितेंद्र सैनी,मीर हसन जोरासी, लक्सर में डॉ. रणवीर नागर, अरविंद प्रधान एवं परवेज अहमद, हरिद्वार ग्रामीण में गुलसन अंसारी, संजय सैनी एवं अरुण चौधरी, यमकेश्वर में साबर सिंह नेगी,सुदर्शन सिंह भंडारी को नियुक्त किया गया। पौड़ी में पंकज पोखरियाल, बलवीर सिंह रावत, कविंद्र इष्टवाल, श्रीनगर में सुरेंद्र सिंह रावत, नितिन बिष्ट, चौबट्टाखाल में संजय डबराल, अमित राज, लैंसडौन में अर्जुन गहरवार, सुनील सेमवाल एवं राकेश शर्मा, कोटद्वार में धीरेंद्र बिष्ट एवं विक्रांत खंतवाल, धारचूला में गिरीश चुफाल एवं बंशीधर भट्ट, डीडीहाट में राहुल राकाया, प्रेमा कोटियाल एवं हेम पंत, पिथौरागढ़ महेश डसीला एवं मनोज टम्टा, गंगोलीहाट में मनोज ओझा एवं अनिल महरा, कपकोट में विनोद कुमार पाठक एवं ललित बिष्ट, बागेश्वर में गोविंद सिंह बिष्ट एवं नरेंद्र कोरंगा की तैनाती की गई इसके अलावा द्वाराहाट में कमल रावत एवं महेंद्र कालाकोटी, सल्ट में दीपक चुनौतिया एवं त्रिलोक सिंह, रानीखेत में नवीन कठायत एवं विरेन्द्र सिंह बिष्ट, सोमेश्वर में आनंद सिंह बिष्ट, नारायण दत्त पाण्डेय एवं जमन सिंह बिष्ट, अल्मोडा में देवेन्द्र सिंह बिष्ट एवं गोपाल सिंह बिष्ट, जगेश्वर में दीप डांगी एवं श्याम सिंह दोसाद, लोहाघाट में पप्पू खर्कवाल एवं बिमला सजवाण, चंपावत में नवीन मुरारी एवं हरीश सिंह बोरा, लालकुंआ में दीप सती, संजय किरोला एवं डॉ. केदार पलेड़िया, भीमताल में भुवन तिवारी एवं सुहेल सिद्धिकी, नैनीताल में शंकर शंकर जोशी, इंद्रपाल आर्य एवं खजान पाण्डेय, हल्द्वानी में हेमन्त पाठक एवं गोविंद सिंह बिष्ट, कालाढूंगी में राजेन्द्र खानवाल, उमेश कबडवाल एवं पुष्कर दुर्गपाल को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं रामनगर में सचिन नेगी, एवं वरुण कपूर, जसपुर में शरीफ अंसारी, शैलेंद्र गहलोत, काशीपुर में पंडित रामदेव शर्मा, मोहम्मद अकरम एवं जाकिर हुसैन, बाजपुर में संदीप सहगल एवं विजय मिठ्ठी, गदरपुर में परिमल राय हरिदेव हैरी, रुद्रपुर में शैलेंद्र शर्मा, नारायण, मनोज खुल्बे, किच्छा में हसनैन मलिक, शीशपाल यादव, सितारगंज में विजेंद्र, प्रकाश सिंह, नानकमत्ता में सत्यपाल सिंह, मंजीत सिंह, जितेंद्र सरस्वती, खटीमा में नरेंद्र आर्य, रमेश रौतेला को विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया।

सिक्योरिटी गार्ड की उपचार के दौरान हुई मौत

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। सिडकुल की एक कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड की तबियत अचानक बिगड़ गई। जानकारी मिलते ही परिजन आ पहुंचे और उन्होंने उसे उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया परंतु उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाऊस भिजवाया। जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय पिन्टू राठौर पुत्र ज्ञान चन्द्र राठौर निवासी वार्ड 02 कृष्णा कालोनी ट्रांजिट कैम्प, मूल निवासी तितर वाली पाखड़ टीन थाना रामपुर सिडकुल के एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करता था। उसके ससुर राम सिंह द्वारा बताया गया कि पिंटू राठौर का ड्युटी के दौरान स्वास्थ्य

खराब हो गया था। जिसे 10 दिसम्बर को कम्पनी के कर्मचारियो द्वारा ईलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों द्वारा हायर सेन्टर सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया था। लेकिन उसके परिजन मृतक उपरोक्त को निजी हॉस्पिटल रुद्रपुर ले गये जहा से पिन्टू को उपचार हेतु उसके परिजन नवोदय अस्पताल बरेली ले गये। जिसके बाद बरेली से लाकर आज शुक्रवार को जिला चिकित्सालय ईलाज हेतु लाया गया जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैम्प थाना के अपर उप निरीक्षक हृदयेश परिहार पुलिसकर्मी के साथ पहुंचे और उन्होंने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाऊस भिजवाया। बताया जाता है कि मृतक पिंटू की पत्नी दिव्यांग है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

बल्लू की माता के निधन पर जताया शोक

रुद्रपुर। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत अरोरा 'बल्लू' की माता श्रीमती भागवन्ती देवी के निधन पर शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में सामाजिक,धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संतप्त परिवारजनों से मिलकर लोगों ने दुख की इस घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें ढांढस बंधाया। रुद्रपुर। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष बलवंत अरोरा 'बल्लू' की माता श्रीमती भागवन्ती देवी के निधन पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। शहर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोग सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर पहुंचे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की।शोक संतप्त परिवार को लोगों ने ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त कीं। शोक व्यक्त करने वालों में रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़, लालकुआं के भाजपा विधायक, लखीमपुर खीरी के भाजपा विधायक योगेश वर्मा, छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी ओमपाल सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय चड्ढा, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष निर्माण मुखर्जी, उत्तराखंड बॉक्सिंग संघ के महामंत्री खोलिया जी, नगर पालिका रुद्रपुर की पूर्व चेयरमैन मीना शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा, सीपी शर्मा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप चीमा, विवेक सक्सेना, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेश परिहार, कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, लखनऊ मेडिकल कालेज के डायरेक्टर डॉ. आनंद मिश्रा, जनता इंटर कालेज के प्रबंधक पवन अग्रवाल, उद्योगपति रोहतास बत्रा, हरीश मुंजाल, संघ के जिला व्यवस्था प्रमुख राजकुमार खनिजों, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, भूरारानी की पूर्व प्रधान रामकिशन खेड़ा, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ आईएएस आशीष गोयल समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। सभी ने दिवंगत भागवन्ती देवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की।

पेज एक का शेष...

देवभूमि में नहीं पनपने देंगे.........जनपद नैनीताल की अन्य विकास योजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यस हुआ। श्री धामी ने कहा कि देव भूमि को देश विदेश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है इसके साथ ही राज्य में सभी पौराणिक मन्दिरों के पुर्नउद्धार व सौदर्यीकरण का भी कार्य किया जा रहा है। उन्होने कहा कि देव भूमि से पलायन रोकने के लिए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आने लगे है श्री धामी ने कहा कि सरकार स्थानीय उत्पादकों लगातार प्रोत्साहन दे रही है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मात्र शक्ति द्वारा निर्मित वस्तुए देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बना रही है जिससे प्रभावित होकर कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी ऐसे उत्पाद खरीदने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कई चुनौतियों का सामना करने के बाबजूद भी प्रदेश आज विकास की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम को विधायक रामसिंह कैड़ा सहित कई वक्ताओं ने सम्बोधित किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल, मनोज साह, रंजन बर्गली, कमल जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी तथा हजारों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। इससे पूर्व कार्यक्रम में मौजूद हजारों क्षेत्रवासियों द्वारा मुख्यमंत्री श्री धामी का ढोल-नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ गर्मजोशी से स्वागत करते हुये भव्य अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सीएम धामी ने शिलापट्ट पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर जनता को नई परियोजनाओं की सौगात दी।

धामी ने नैनीताल जिले को........मार्ग सुधारीकरण का निर्माण कार्य, 19.48 करोड़ से 50 बैड क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, 8.43 करोड़ से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय हल्दूचौड में पुस्तकालय, बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण, 1.46 करोड़ से निराश्रित गौवंश के लिए ग्राम पुछडी में गौशाला निर्माण, 61.38 लाख से रा.उ.मा.वि. जाडापानी भीमताल में पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का लोकापर्ण किया।साथ ही मुख्यमंत्री ने 41.60 करोड़ से 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने 5.35 करोड़ से लालकुआ में राजकीय महाविद्यालय में परीक्षा भवन निर्माण, 97.72 लाख से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में चाहरदीवारी निर्माण, 1.5 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में स्वीमिंग पुल पर टेंसाईल शेड एवं पूल कवरिंग कार्य, 46.54 लाख से रा.उ.मा.वि. झड़गांव में भवन निर्माण कार्य, 75 लाख की लागत से ओखलकांडा में सभागार कक्ष, 45 लाख की लागत से रामनगर में टाईप-4 आवासीय भवन निर्माण, 9.81 करोड़ से बेतालघाट में दूनीखाल से रातीघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण, 8.19 करोड़ से पंगोट दैचोरी मार्ग का नवनिर्माण, इंदिरा गांधी अंतराष्ट्रीय स्टेडियम गौलापार में सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की योजनाओं का शिलान्यास किया।

दर्दनाक हादसा-चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान प्रीत यादव (28) पुत्र राजेश यादव तथा राहुल (18) पुत्र गौरी शंकर यादव, दोनों निवासी स्यानी थाना नंदग्राम, गाजियाबाद के रूप में हुई है।घायलों में विवेक यादव (23), दीपांशु निवासी नगला सुदमा (मैनपुरी), प्रीत की पत्नी ज्योति (27) तथा उनकी दो बेटियांअन्वेया उर्फ परी (3 वर्ष 6 माह) और किट्टू (1.5 वर्ष) शामिल हैं।

लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार की हो रही सराहना: गुंजन

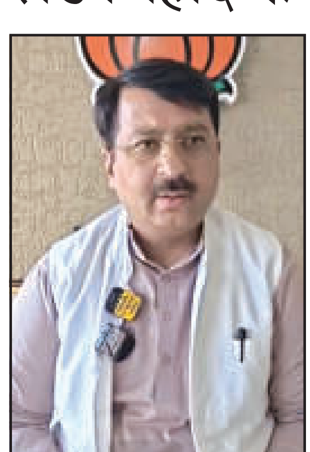

गदरपुर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रदेश की डेमोग्राफी के संरक्षण और 'लैंड जिहादियों' के खिलाफ की जा रही कठोर और निर्णायक कार्रवाइयों की भरपूर सराहना की। गुंजन सुखीजा ने मुख्यमंत्री धामी के प्रयासों को राज्य के मूल स्वरूप और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम बताया। उन्होंने बल दिया कि प्रदेश की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखना और अवैध गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रेस वार्ता के दौरान, गुंजन सुखीजा ने गुलरभोज स्थित ठंडा नाले में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के ऊपर हुई त्वरित कार्यवाही को लेकर धामी सरकार की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी जमीनों को गलत तरीके से बेचकर अपना निजी फायदा किया जा रहा था, जिसमें मुख्य आरोपी अशगर अली को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सुखीजा ने अशगर अली को संरक्षण देने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सख्त और त्वरित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। गुंजन सुखीजा ने मुख्यमंत्री धामी की दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा धामी सरकार जिस तरह से प्रदेश हित में कड़े और ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, वह सराहनीय है। हमारी सरकार उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गुलरभोज ठंडेनाले जैसे संवेदनशील मामलों में लिप्त अशगर अली पर हुई कार्रवाई प्रदेश में 'लैंड जिहाद' को जड़ से समाप्त किया जा सके और कानून का राज स्थापित हो सके का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी है। मुख्यमंत्री धामी जी ने दिखा दिया है कि राज्य के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

प्रदेश में सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए : डीजीपी

देहरादून। एक सप्ताह के भीतर राज्य के सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। डीजीपी दीपम सेठ ने गोवा अग्निकांड के मद्देनजर सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके लिए आगामी क्रिसमस और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिए भी कहा है। पुलिस के मुखिया ने शीतकालीन चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और संचालन को सशक्त बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। डीजीपी बृहस्पतिवार को पुलिस मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि गोवा में पिछले दिनों एक पब में अग्निकांड हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। राज्य में देहरादून, नैनीताल, मसूरी आदि जगहों पर क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भीड़ रहती है। पूरे प्रदेश में कैफे, पब, बार, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, इवेंट वेन्यू, मॉल आदि समेत ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए जहां पर लोगों की भीड़ रहती है। इस दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए उपलब्ध सभी उपकरणों की उपलब्धता, कार्यक्षमता और पर्याप्तता की गहन जांच की जाए। सार्वजनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थापित सभी फायर हाईड्रेंट को पूरी तरह से क्रियाशील रखने के निर्देश भी डीजीपी ने दिए। इसके साथ ही जहां पर कर्मचारियों के पास फायर सेफ्टी उपकरणों को चलाने का प्रशिक्षण नहीं है उन्हें तत्काल प्रशिक्षण दिया जाए। प्रतिष्ठानों में आपातकाल के समय बाहर निकलने के रास्ते पर कोई अवरोध तो नहीं इस बात की जांच भी की जाए। मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ की जाए। शीतकालीन चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए जिलों को व्यापक निर्देश दिए। गंभीर अपराधों में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक प्रभावी अभियान चलाया जाए। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वाणिज्यिक मात्रा वाले लंबित मुकदमों का निस्तारण तय समय में किया जाए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को कुर्क करने का अभियान चलाया जाए। पुलिस कर्मियों की पदोन्नति में तेजी लाई जाए।

संस्थापक- स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रुद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

उधम सिंह नगर पुलिस को 'सलाम', फिर साधा 'सटीक निशाना'

सुपर कॉप मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में उधम सिंह नगर पुलिस ने सफलता पूर्वक किया अपना 35 वां एनकाउंटर, इस दफा गदरपुर थाना पुलिस ने गुरबाज सिंह के साथ खेला एनकाउंटर

-अर्श-

रुद्रपुर। उधम सिंह नगर जिले के पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा की जिले में तैनाती के बाद, जनपद की पुलिस का स्वभाव एवं कार्य प्रणाली तो बदली ही है, साथ ही साथ अपराधियों के स्वभाव में भी आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन सामने आया है। पहले जिले का अपराधी पुलिस की परछाई को देखकर ही दूर से किनारा कर लेता था, लेकिन नए उधम सिंह नगर का हर दूसरा तीसरा अपराधी आजकल पुलिस को देखते ही फायर झोंक देता है। मजे की बात तो यह है कि फायर करते समय उधम सिंह नगर जिले के अपराधी इस बात का पूरा-पूरा ख्याल रखते हैं कि उनकी चलाई गोली गलती से भी किसी पुलिसकर्मी को ना लगे। और तो और, जिले के अपराधियों द्वारा भागते समय हड़बड़ी में भी चलाई गई गोली भूल कर भी, ना किसी पुलिस कर्मी को छूती है और ना ही किसी आम व्यक्ति अथवा किसी जीव जंतु को। ऐसा जान पड़ता है जैसे नए उधम सिंह नगर का अपराधी साहसी तो हुआ है ,मगर अभी वह पूरी तरह हिंसक नहीं हुआ। इस बदलते दौर में भी अभी उसका महात्मा गांधी की अहिंसा पर पूरा विश्वास है। कथाचित यही कारण है कि गोली चलाते समय जनपद के अपराधी इस बात का पूरा एहतियात रखते हैं कि तमंचे की गोली किसी को हताहत ना करे। और, उधम सिंह नगर के पुलिस के जांबाज जवानों की तो बात ही अलग है। ऐसे अद्भुत प्रदर्शन पर अब तो पुलिस के निशानेबाजों को सलाम करने को दिल करता है। भई, क्या निशाना लगाते हैं ? उनकी चलाई गई गोली हर बार ठीक घुटने के नीचे ही लगती है। मजाल है कि गोली का जख्म लेश मात्र भी इधर-उधर हो जाए। गजब की महारत हासिल है उधम सिंह नगर पुलिस के जवानों को निशानेबाजी में ।भारत सरकार अगर कहीं देश के निशानेबाजों को उधम सिंह नगर पुलिस से निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिलाने लगे ,तो हमारे निशानेबाजों को ओलंपिक में चार- छह गोल्ड मेडल तो चुटकियों में मिल जाए। किसी को निशानेबाजी पर कंट्रोल का नमूना देखना है तो उधम सिंह नगर पुलिस की हालिया मुठभेड़ पर एक नजर मार ले। उसे पता चल जाएगा कि आत्मरक्षा की कवायद एवं भागम भाग में भी निशानेबाजी पर पूरा कंट्रोल कैसे रखा जाता है। हालांकि, कई बार कुछ लोग उधम सिंह नगर पुलिस और अपराधियों की इस म्युचुअल मुठभेड़, अपराधी को एक ही स्थान पर गोली लगने, मुठभेड़ के बाद अस्पताल का एक जैसा सीन ,अपराधी के सामने खड़े होकर हर बार एक ही अंदाज में अपराधी को घूरते हुए पुलिस कप्तान आदि को देखकर सवाल भी खड़ा करते हैं ,पर हम ऐसे लोगों की बातों पर कोई खास तवज्जो नहीं देते। हम तो दाद देना चाहेंगे उधम सिंह नगर पुलिस के जांबाज निशानेबाजों को। भाई मजा आ गया। महज 35 महीने की

अवधि में 35 वां एनकाउंटर। वह भी बिल्कुल सटीक निशानेबाजी के साथ, ऐन घुटने के नीचे। बधाई! हो उधम सिंह नगर पुलिस। इस बार के एनकाउंटर-एनकाउंटर खेल मैं बेस्ट परफॉर्मेंस का पुरस्कार गदरपुर थाना के नाम।

चोरों ने मिठाई की दुकान से उड़ाई नगदी व सामान

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। अज्ञात चोरों ने गुरूवार की रात्रि किच्छा मार्ग पर स्थित एक मिठाई की दुकान के कुंडे तोड़कर दुकान से हजारों रूपये की नगदी, सामान तथा मोबाईल आदि चोरी कर लिया। प्रात: घटना की जानकारी मिलने पर रम्पुरा चौकी पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जिसमें दो नाबालिग व एक युवक चोरी की घटना को अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भूतबंगला निवासी युवक की किच्छा मार्ग पर चौकी के समीप स्वीट फोर यू नाम से मिठाई की दुकान है। उसने बताया कि गुरूवार की रात्रि वह दुकान बंद करके घर गया था। आज जब वह दुकान

खोलने आया तो देखा दुकान के ताले कुंडे से अलग निकले हुए हैं। जब दुकान के भीतर गया तो देखा सारा सामान अस्त व्यस्त है गल्ला खुला हुआ है और दुकान से बहुत सारा सामान गायब है। उसने बताया कि अज्ञात चोरों ने बिना ताला तोड़े शटर का कुंड़ा तोड़ा और अन्दर आकर पहले गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 35 हजार रूपये चोरी कर लिए। इसके बाद कुछ ही देर में चोर फिर से दुकान के भीतर आये और लगभग 40 हजार रूपये कीमत का सामान जिसमें उसका मोबाईल, कोल्ड ड्रिंक, चोकलेट, मिठाई आदि सामान शामिल है बैग में भर कर ले गये। उसका कहना है कि यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसमें दो नाबालिग व एक युवक चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब हो कि घटनास्थल के पास ही रम्पुरा चौकी व एएसपी आवास भी मौजूद हैं। इस मार्ग पर रात भर लोगों व वाहनों की आवाजाही भी लगी रहती है। लेकिन बेखौफ चोरों ने घटना को दिया।

सड़कों में टेंट लगाकर जमावड़े की नहीं मिलेगी अनुमति

सितारगंज। सड़कों में टेंट लगाकर किसी भी प्रकार के जमावड़े के लिए पुलिस, प्रशासन अनुमति नहीं देगा। सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने यह निर्णय लिया हैं। इस इस तरह के धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन के लिए अलग से जगह विभाग चिन्हित करेंगे। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने बताया कि सड़कों में निरंतर यातायात व्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए किसी भी प्रकार के जमावड़े की मनाही हैं। सड़कों में टेंट लगाकर धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक आयोजन के लिए पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। इस तरह के आयोजन और जमावड़े के लिए अलग से भूमि चिन्हित कर अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षणिक और सांकेतिक कार्यक्रमों के लिए छूट मिलेगी। कोतवाल सुंदरम शर्मा ने यह निर्णय यातायात सुरक्षा और जमावड़े में आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर लिया हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के बाद विभिन्न तरह के सुरक्षा प्रबंधों के मानक तय किए जाते हैं। उन्होंने बिना अनुमति के सड़कों में टेंट लगाकर भीड़ एकत्रित करने पर विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नागरिक छोड़ रहे हैं भारतीय नागरिकता

18.79 लाख भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से त्यागी अपनी नागरिकता

काशीपुर। 18 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने वर्ष 2011 से 2023 तक 13 वर्षों में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त की हैं। वर्ष 2022 तथा 2023 में तो यह दर प्रतिवर्ष दो लाख नागरिकों से भी अधिक हैं। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) को विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से हुआ हैं। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी से भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों की नागरिकता प्राप्त करने वालों की संख्या की सूचना चाही थी। इसके उत्तर में विदेश मंत्रालय के जन सूचना अधिकारी/अवर सचिव तरूण कुमार ने अपने पत्रांक 551 से उत्तर उपलब्ध कराया है। जन सूचना अधिकारी ने राज्यसभा में कपिल सिब्बल तथा डा0 जोहन बिट्स के प्रश्नों के उत्तर में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

होने को लिखित करते हुये उसका इंटरनेट लिंक उपलब्ध कराया है।श्री नदीम द्वारा उक्त लिंक से सांसदों के प्रश्नों के उत्तर डाउनलोड करने पर वर्ष 2011 से 2023 तक भारत की नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों की संख्या प्रकाश में आयी है। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2022 में पिछले 13 वर्षों में सर्वाधिक 2,25,620 भारतीय नागरिकों ने अपनी भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ी है। दूसरे स्थान पर वर्ष 2023 में 2,16,219 भारतीय नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी हैं। पिछले 13 वर्षों में सबसे कम नागरिकता छोड़ने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 85256 वर्ष 2020 में रही हैं। वर्ष 2011 में 1,22,819, वर्ष 2012 में 120,923, वर्ष 2013 में 1,31,405, वर्ष 2014 में 1,29,328, वर्ष 2015 में 1,31,489, वर्ष 2016 में 1,41,603, वर्ष 2017 में 1,33049, वर्ष 2018 में 134561, वर्ष 2019 में 1,44017, वर्ष 2020 में 85256, वर्ष 2021 में 163370, वर्ष 2022 में 225620, वर्ष 2023 में 2,16,219 भारतीय नागरिकों ने स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार भारतीय नागरिकता छोड़कर विश्व के 135 देशों की नागरिकता इन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी है। जिन देशों की नागरिकता भारतीय नागरिकता छोड़कर भारतीयों द्वारा प्राप्त की गयी है उनमें जहां पड़ोसी देश, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है, वहीं विकसित माने जाने वाले देश यू के, यू.एस.एस. रूस, चीन, इटली, फ्रांस, जर्मनी व जापान तथा आर्थिक सम्पन्न वाले देशों में इराक, इरान, इटली, तुर्की, यमन, जम्बिया, कजाकश्तान, केनिया, मलेशिया, मालद्वीव, ओमान, कतर, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, सुडान देश भी शामिल है।